

कुशल भारत का नरिमाण

यह एडिटरियल 22/04/2022 को 'हद्वि बिजनेस लाइन' में प्रकाशित "Skilling Efforts Need To Be Scaled Up" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में कौशल विकास के लिये की गई पहलों और कौशल उन्नयन से संबद्ध चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

प्रौद्योगिकीय कायापलट के साथ नए तरह के रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है जिनके लिये विभिन्न प्रकार के विशेष कौशलों की आवश्यकता होती है। इन हायर-एंड नौकरियों के लिये नेटवर्कगि, क्वालिफिकेशन, प्रॉब्लम-सॉल्विंग जैसे अधिकाधिक 'मानवीय' कौशल की ज़रूरत पड़ती है।

- चूँकि भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ औसत आयु 29 वर्ष है (चीन के 37 वर्ष और जापान के 48 वर्ष की तुलना में), इसमें युवा आबादी के इस पूल को मानव पूंजी में बदलने की क्षमता है, बशर्ते उनकी शिक्षा एवं कौशल नरिमाण पर लगातार ध्यान दिया जाए।
- लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जहाँ देश के कार्यबल में हर वर्ष 12 मिलियन लोग जुड़ते हैं, 4% से भी कम को कभी कोई औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। भारत की कार्यबल तैयारी (Workforce Readiness) का स्तर विश्व में न्यूनतम में से एक है और वदियमान प्रशिक्षण अवसंरचना का एक बड़ा भाग उद्योग की आवश्यकताओं के लिये अप्रासंगिक है।

भारत का मानव संसाधन परिदृश्य

- वर्ष 2021 में लगभग 135 करोड़ भारतीयों में से लगभग 34% (46.42 करोड़) 19 वर्ष से कम आयु के थे और लगभग 56% (75.16 करोड़) 20 से 59 वर्ष के बीच के थे।
 - वर्ष 2041 तक यह जनसांख्यिकी बदल जाएगी लेकिन 20-59 आयु वर्ग की अपनी 59% (88.97 करोड़) आबादी के साथ भारत फिर भी विश्व में मानव संसाधनों का सबसे बड़ा पूल रख सकता है।
- अगले दो दशकों में औद्योगिकृत विश्व में श्रम शक्ति में 4% की गतिवृद्धि की उम्मीद है, जबकि भारत में इसमें लगभग 20% की वृद्धि होगी।
 - भारत प्रतिभा और कौशल का आपूर्तिकर्ता बन सकता है यदि सभी आयु समूहों में इसका कार्यबल रोजगार योग्य कौशल से लैस हो और जो तेज़ी से बदलते तकनीकी पारिंत्र के साथ तालमेल बिठा सकता हो।

भारत के मानव संसाधन के कौशल नरिमाण की स्थिति:

- राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति (National Policy on Skill Development and Entrepreneurship) पर वर्ष 2015 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि भारत में कुल कार्यबल के केवल 4.7% ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया था, जबकि अमेरिका में यह 52%, जापान में 80% और दक्षिण कोरिया में 96% था।
- राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (National Skill Development Corporation- NSDC) द्वारा वर्ष 2010-2014 की अवधि के लिये किये गए एक कौशल अंतराल अध्ययन से पता चला कि वर्ष 2022 तक 24 प्रमुख क्षेत्रों में 10.97 करोड़ कुशल जनशक्ति की अतिरिक्त नविल वृद्धिशील आवश्यकता होगी।
 - इसके अलावा, 29.82 करोड़ कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के कामगारों की स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग की आवश्यकता होगी।

कौशल विकास के लिये की गई प्रमुख पहलें

- **प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना:** समय के साथ प्रशिक्षण और कौशल के लिये एक पर्याप्त वृहत संस्थागत प्रणाली का विकास हुआ है। इसमें 15,154 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ ITIs (11,892 नजी संस्थानों सहित), 36 क्षेत्र कौशल परिषद, 33 राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान और NSDC के साथ पंजीकृत 2,188 प्रशिक्षण भागीदार शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:** सरकार की फ्लैगशिप 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' वर्ष 2015 में ITIs के माध्यम से और अप्रेंटिसशिप योजना (Apprenticeship Scheme) के तहत अल्पकालिक प्रशिक्षण व कौशल प्रदान करने के लिये शुरू की गई थी।
 - वर्ष 2015 से अब तक सरकार इस योजना के तहत 10 मिलियन से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित कर चुकी है।

- **‘संकल्प’ और ‘स्ट्राइव’:** संकल्प कार्यक्रम (SANKALP programme)—जो ज़िला-स्तरीय स्कलिंग पारितंत्र पर केंद्रित है और ‘स्ट्राइव योजना’ (STRIVE project)—जसिका उद्देश्य ITIs के प्रदर्शन में सुधार करना है, अन्य महत्त्वपूर्ण कौशल नरिमाण हस्तकषेप हैं।
- **वभिनिन मंत्रालयों की पहल:** 20 केंद्रीय मंत्रालयों/वभिगों द्वारा लगभग 40 कौशल विकास कार्यक्रम कार्यान्वति कयि जा रहे हैं। कुल कौशल नरिमाण में ‘कौशल विकास और उद्यमति मंत्रालय’ का योगदान लगभग 55% है।
 - इन सभी मंत्रालयों की पहल के परिणामस्वरूप वर्ष 2015 से लगभग चार करोड़ लोगों को वभिनिन औपचारिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षति कयि गया है।
- **कौशल नरिमाण में अनविर्य CSR व्यय:** कंपनी अधनियम, 2013 के तहत अनविर्य CSR व्यय के कार्यान्वयन के बाद से भारत में नगिमें ने वविधि सामाजिक परयोजनाओं में 100,000 करोड़ रुपए से अधिक का नविश कयि है।
 - इनमें से लगभग 6,877 करोड़ रुपए कौशल नरिमाण और आजीविका उन्नयन परयोजनाओं पर खर्च कयि गए हैं। इस क्रम में महाराष्ट्र, तमलिनाडु, ओडशिा, कर्नाटक और गुजरात शीर्ष पाँच प्राप्तरता राज्य रहे।
- **स्कलिंग के लयि ‘तेजस’ पहल:** हाल ही में स्कलि इंडयि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ‘तेजस’ (TEJAS- Training for Emirates Jobs And Skills) को वदिशी भारतीयों को प्रशिक्षति करने के लयि दुबई एक्सपो, 2020 में लॉन्च कयि गया था।
 - यह परयोजना भारतीयों के कौशल नरिमाण, प्रमाणन और वदिश में नयिोजन पर केंद्रति है तथा भारतीय कार्यबल को यूईई में कौशल और बाज़ार आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाने के लयि प्रयासरत है।

कौशल विकास के संबंध में वदियमान चुनौतयिाँ:

- **बुनयिदी शकषिा की कमी:** वर्ष 2020 के एक NSO सर्वेक्षण से उजागर हुआ है कि स्कूल या कॉलेज में नामांकति प्रत्येक आठ छात्रों में से एक शकषिा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देता है। इनमें से 63% स्कूल स्तर पर ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।
 - अधिकतम ‘ड्रॉपआउट’ उच्च प्राथमिक (17.5%) और माध्यमिक वदियलय (19.8%) वर्षों में देखने को मलि हैं। 40% से भी कम छात्रों ने उच्चतर माध्यमिक और/या उच्च शकषिा ग्रहण की।
 - बुनयिदी स्तर की शकषिा के अभाव में उच्च स्तर की नौकरयिों के लयि युवा आबादी का कौशल उन्नयन करना कठनि होगा।
- **अप-स्कलिंग/री-स्कलिंग पर फोकस की कमी:** वविधि स्कलिंग पहलों में वृद्धि के साथ भारत ने कार्यबल की कौशल नरिमाण आवश्यकताओं को काफी हद तक संबोधति कर दयि है।
 - हालाँकि, वृहत कामकाजी आबादी की अप-स्कलिंग और री-स्कलिंग आवश्यकताएँ अभी तक प्रायः पूरी नहीं हो सकी हैं।
 - PLFS डेटा 2019-20 के अनुसार, 15-59 आयु वर्ग के 86.1% लोगों को कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ था; शेष 13.9% ने वविधि औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त कयि था।
- **अपर्याप्त प्रशिक्षण सुवधिारै:** NSSO द्वारा कयि गए एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लॉजिस्टिकस, स्वास्थ्य सेवा, नरिमाण, आतथ्य और ऑटोमोबाइल जैसे 20 उच्च-विकास उद्योगों में प्रशिक्षण सुवधिारै की कमी है।
 - भारत में प्रशिक्षण के लयि लगभग 5,500 सार्वजनिक (ITIs के रूप में) और नजिी (ITC के रूप में) संस्थान हैं, जबकि चीन में ऐसे संस्थानों की संख्या 500,000 तक है।
- **कोवडि-19 महामारी:** कोवडि-19 महामारी लघु और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्यवधान के लयि ज़मिेदार रही, जसिसे लाखों छात्रों को नुकसान हुआ है।
 - कोवडि की पहली लहर में 30,000 से अधिक ITIs और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों ने अस्थायी रूप से प्रशिक्षण केंद्रों को बंद कर दयि, जसिसे देश भर में 50 लाख उम्मीदवारों के लयि अवसरों का नुकसान हुआ।

भारतीय कार्यबल की अप-स्कलिंग के लयि क्यि कयि जा सकता है?

- **ड्रॉपआउट की प्रवृत्तको बदलना:** NSDC द्वारा आकलति कौशल आवश्यकताओं के साथ स्कूल/कॉलेज ड्रॉपआउट छोड़ने की प्रवृत्तयिों को संयुक्त कर देखें तो स्पष्ट है कि हमारी सकारात्मक जनसांख्यिकी का लाभ उठाने के लयि उल्लेखनीय प्रयास करने होंगे।
 - ग्रामीण या शहरी परविश पर वचिार कयि बनिा पब्लिक स्कूल प्रणाली को यह सुनिश्चति करना चाहयि कि प्रत्येक बच्चा हाई स्कूल तक की शकषिा पूरी करे और उसे बाज़ार की मांग के अनुरूप उपयुक्त कौशल, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शकषिा की ओर आगे बढ़ाया जाए।
 - मैसवि ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOCs) के साथ वर्चुअल क्लासरूम को स्थापति करने हेतु नई प्रौद्योगिकी की तैनाती से उच्च शकषिा कार्यबल प्राप्त करने में मदद मलैगी।
- **लक्ष्यों में अप-स्कलिंग को शामिल करना:** इस बात के पर्याप्त प्रमाण मौजूद हैं कि पहले से नयिोजति कार्यबल की अप-स्कलिंग से अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादकता, शर्मिकों के लयि उच्च आय और फर्मों के लयि उच्च लाभप्रदता की स्थति प्राप्त हो सकती है।
 - इसी प्रकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PPP प्रारूप में अप-स्कलिंग पहलों को प्राथमिकता दे सकती है। यूके, जर्मनी और ऑस्ट्रेलया जैसे कई देशों में उनके कौशल प्रयासों में औद्योगिक क्षेतर के अभकिरताओं की सकरयि भागीदारी होती है।
 - अपने मौजूदा कार्यबल के कौशल की गुणवत्ता को बढ़ाकर ही भारत अपने आकांक्षी विकास लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम हो सकेगा।
- **कॉरपोरेट क्षेतर को शामिल करना:** कौशल विकास में नविश कॉरपोरेट भारत के साथ-साथ समग्र रूप से राष्ट्र के लयि एक लाभप्रद स्थति होगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में NASSCOM की एक रपिर्ट ने पुष्टि की कि कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नविश करने से परविय पर 600% से अधिक का रटिर्न प्राप्त हुआ।
 - भारतीय नगिम उद्योग-वशिषिट कौशल प्रदान करने के लयि उद्योग-स्तरीय सहयोग पर वचिार कर सकते हैं।
 - बड़े उद्योग बड़े शहरों से लेकर छोटे ज़िलों और गाँवों तक अपने कार्यकरण का वसितार कर सकते हैं। यह [आत्मनरिभर भारत](#) अभयान की सफलता के लयि एक बड़ा कदम साबति होगा।

अभ्यास प्रश्न: “भवषिय के कार्यबल के रूप में भारत के युवाओं की स्कलिंग, अप-स्कलिंग और री-स्कलिंग सरकार के ‘आत्मनरिभर भारत’ के दृषटकिण की सफलता में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभिएगी।” चर्चा कीजयि।

